सख्ती | केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा- विज्ञापन नीति बनाओ और सबको बताओ

जनता के पैसे से क्यों छप रहे हैं नेताओं के विज्ञापन?

दैनिक भास्कर 19-1-15

सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है- सरकारी विज्ञापन में नेताओं के फोटो न छपें

एजेंसी|नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरें छपने पर सख्त रवैया अपनाया है। आयोग ने कहा है कि सरकार इस संबंध में जल्द से जल्द नीति बनाए। आरटीआई कानून के तहत इसे सार्वजनिक करे।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अग्रवाल ने सरकारी विज्ञापनों में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित और पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान के फोटो पर लोकायुक्त की सिफारिशों की जानकारी मांगी है। इससे जुड़े मामले में आचार्युलु ने कहा कि अग्रवाल ने जो मुद्दा उठाया है, वह जनहित का है। इस पर प्रभावी कार्रवाई हुई तो जनता के पैसों का नेताओं के फोटो वाले विज्ञापनों पर फिजूल इस्तेमाल रोका जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना है सरकार को

कॉमन कॉज संगठन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों के राजनीतिक दुरुपयोग को गंभीरता से लिया था। अक्टूबर में प्रो. एनआर माधव मेनन की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति बनाकर नई गाइडलाइन बनाने को कहा था। समिति ने जनवरी के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट एडवरटाइजमेंट (कंटेंट रेग्युलेशन) गाइडलाइंस 2014 सुझाई है। इसके मुताबिक, सरकारी विज्ञापन में सत्ताधारी पार्टी का नाम, चिह्न या लोगो, झंडा और पार्टी के किसी नेता का फोटो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विज्ञापन में नेताओं के फोटो छापने से बचना होगा। यदि किसी का फोटो छापना जरूरी है तो सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के फोटो छपना चाहिए।

सरकारी पैसे से नेता चमका रहे हैं छवि

- 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे एनडीए सरकार ने 2004 में शाइनिंग इंडिया कैम्पेन पर।
- 200 करोड़ रुपए खर्च किए यूपीए-1 सरकार ने 2009 में भारत निर्माण कैम्पेन पर।
- 285 करोड़ रुपए खर्च किए यूपीए-2 सरकार ने 2012 से 2014 के बीच भारत निर्माण कैम्पेन पर।

आरटीआई का जवाब न देने पर सोनिया गांधी को नोटिस

सीआईसी ने आरटीआई का जवाब न देने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि उनकी पार्टी ने आरटीआई के तहत जानकारी देने के आयोग के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया? सीआईसी ने पिछले साल छहों राष्ट्रीय पार्टियों- कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, सपा और एनसीपी को पब्लिक अथॉरिटी बताते हुए आरटीआई कानून के दायरे में लाने का आदेश दिया था। लेकिन किसी भी पार्टी ने इस तरह के आवेदनों का जवाब देने की कोई व्यवस्था नहीं की। न तो कानून बदला और न ही आयोग के आदेश को किसी हाईकोर्ट में चुनौती दी। आरटीआई एक्टिविस्ट आरके जैन ने पिछले साल फरवरी में कांग्रेस को आवेदन दिया था। लेकिन जवाब न आने पर सीआईसी की शरण ली।

देश में बना पहला हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस'

दैनिक..., 19-1-15

देश में बना पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस शनिवार को वायुसेना में शामिल हो गया। इसे भारतीय रक्षा एवं वैमानिकी के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है। 32 साल पहले देश में ही हल्के लड़ाकू विमान बनाने के इस मुश्किल और महत्वाकांक्षी सफर की शुरुआत हुई थी। साल 1983 में भारत सरकार ने मिग-21 विमान की जगह स्वदेशी तेजस को विकसित करने का जिम्मा डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च डेवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) को सौंपा था, लेकिन तमाम परेशानियों से जूझते हुए यह अब जाकर विकसित हुआ है। हालांकि अब भी उन्नत तकनीक से लैस तेजस को आने में समय लगेगा। वहीं अभी इसको शुरुआती परिचालन की ही मंजूरी मिली है। इसका मतलब है कि यह विमान विभिन्न हालात में उड़ान भर सकता है। इसे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने में एक साल और लगेगा। उसके बाद ही यह वायुसेना में पूरी तरह काम कर सकेगा। इसका उत्पादन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड कर रहा है। तेजस पांच तरीके से दुश्मनों के ठिकाने पर धावा बोल सकता है। वर्तमान में वायु सेना के पास पुराने जमाने के 10 मिग-21 विमानों का बेड़ा है। एक बेड़े में 20-21 विमान मौजूद हैं। इसके स्थान पर अब तेजस के छह बेड़ों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद वायुसेना की धार और मजबूत हो जाएगी। हालांकि तेजस के साथ चुनौतियां भी हैं। दुनिया में जो आधुनिक युद्धक विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे यह बहुत पीछे है। इसमें कई तकनीक को सिर्फ दो सप्ताह पहले ही जोड़ा गया है। आधे रास्ते में आसमान में ही ईंधन को भरना, लंबी दूरी तक मिसाइल को ले जाना जैसी कई ऐसी चीजें हैं जो अगले साल फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद ही संभव हो पाएंगी। आज देश अपनी रक्षा तैयारियों को हर स्तर पर मजबूत कर रहा है। जल्द ही फ्रांस के साथ राफेल सौदे को अंतिम रूप दिया जाना है। 15 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत 126 राफेल फाइटर जेट भारत को चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा भारत रूस के साथ मिग-29 श्रेणी के अत्याधुनिक विमानों को भी खरीदेगा। वहीं भारत खुद पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने की योजना बना रहा है जो किसी भी रडार से बच निकलेगा। अब भारत देश में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण करने में रुचि लेने लगा है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में 49 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति दी है। गत वर्ष देश में निर्मित युद्धपोत से लेकर पनडुब्बी तक को नौसेना में शामिल किया गया था। वहीं अग्नि, पृथ्वी आदि मिसाइलें थल सेना की ताकत में इजाफा कर ही चुकी हैं। भारत एक परमाणु शक्ति पहले ही बन चुका है। दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के लिए यह सुखद शुरुआत है। आज भी भारत अपनी जरूरतों का करीब 70 फीसदी रक्षा उपकरण आयात करता है और शेष जिनका यहां उत्पादन होता भी है उनमें भी ज्यादातर विदेशी कलपुर्जे ही लगे होते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन की राह में कदम बढ़ा चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही विदेशों पर निर्भरता घटेगी।